MODERNISING COAL MINING

*626 SHRI KRISHAN KANT
SHRI SYED AHMAD
SHRI KOTA PUNNAIAH
SHRI D P SINGH
SHRI CHANDRA SHEKHAR
DR Z A AHMAD

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state

(a) the progress so far made in modernising coal mining, and

(b) whether the private sector collieries are cooperating in this regard ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI S MOHAN KUMARAMANGLAM) (a) and (b) A statement giving the required information is laid on the Table of the House

STATEMENT

(a) and (b) So far as public sector is concerned, a majority of the coal mines under the National Coal Development Corporation Ltd and the Singareni Collieries Company Ltd are mechanised and have been modernised to the extent necessary under the prevailing conditions Work of modernising the mines recently acquired by the Bharat Coking Coal Ltd is still at the Planning stage

In the private sector, coal industry spent about Rs 14 17 crores out of the World Bank Loan of Rs 16 67 crores during the Third Plan period, for importing coal mining machinery and equipment, etc TISCO has launched a programme for re-structuring and modernising their coal mines producing coking coal needed for their steel plants TISCO had taken up a programme of modernising and expansion of their two coal mines in Jharia with the help of World Bank Loan. This work has progressed well and one large coal washery has already been functioning treating coals from these two mines. Some private sector Companies have also modernised their mines but the majority of private sector Companies have continued with prevalent manual methods The 'Planning Group on the Fourth Five Year Plan Programme for Coal" did no envisage the necessity for additional investment for further mechanisation of the private sector non-coking coal mines (except equipment) during the IV Plan period as the demand for coal, particularly non-coking coal, did not come up to the expected level

कोयले का वितरण

*627. **श्री लाल आडवाणी :**
श्री मानसिंह वर्मा :
श्री ना. कृ. शेजवलकर :
श्री जगदीशप्रसाद माथुर :
श्री डी. के. पटेल :
श्री रत्तनलाल जैन :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा बिहार की कोयल खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिए जाने के पश्चात् कोयले के उत्पादन और विभिन्न इस्पात कारखानों को इसके वितरण तथा कर्मकारों के वेतन था भत्तों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

†[DISTRIBUTION OF COAL

*627 SHRI LAL K ADVANI
SHRIMAN SINGH VARMA :
SHRI N K SHEJWALKAR :
SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR
SHRI D K PATEL
SHRI RATTAN LAL JAIN

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state what steps are being taken by Government to improve the production and distribution of coal to various steel factories and with regard to pay and allowances of workers after the take over of coal mines in Bihar by Goverhment ?]

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमगलम्) अपेक्षित जानकारी देनेवाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अगस्त 1972 में कोककारी कोयले के दुर्लभ संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण तथा लौह और इस्पात उद्योग की इस प्रकार के कोयले के लिए बढती हुई अपेक्षाओं की पूर्ति के प्रयोजनार्थ देश में 214 कोककारी कोयला खानों का उनके पुनर्गठन और पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से राष्ट्रीयकरण किया गया है। यद्यपि केन्द्रीय

†[ ] English translation.

सरकार द्वारा इन खानो का प्रबन्ध अक्तूबर 1971 मे ग्रहण किया गया था तथापि उनके पुनर्गठन और पुनर्निर्माण के लिए कोई प्रभावी कदम नही उठाए जा सके क्योकि केन्द्रीय सरकार अगस्त 1972 मे खानो के राष्ट्रीयकरण होने तक, प्राईवेट स्वामियो की ओर से अभिरक्षक के रूप मे कार्य कर रही थी। इस अवधि के दौरान इन खातो से प्राप्त उत्पादन की औसतन मात्रा लगभग 10 8 लाख टन प्रति माह के स्तर पर स्थिर रही। यह उस उत्पादन से कुछ ही अधिक है जो अक्तूबर, 1971 मे प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व के दो महीनो के दौरान उत्पादन था। नए प्रबन्ध द्वारा प्रारभिक कठिनाइयो के सामना किए जाने पर भी यह सफलता प्राप्त हो सकी है। कोककारी कोयले के परिवहन और वितरण के लिए प्रक्षालन-शालाओ और इस्पात सयत्रो को पर्याप्त सख्या मे वैगन उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए गए थे और इस्पात सयत्रो मे इस प्रकार के कोयले की कमी की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है।

प्रबध ग्रहण की गई कोककर कोयला खानो के पुनर्गठन और पुनर्निर्माण की योजनाए जो अनुध्याताधीन थी अब अगस्त 1972 मे खानो के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप कार्यान्वित की जा सकती है। जनवरी 1972 मे भारत सरकार और पोलैड जन गणतत्र के मध्य हस्ताक्षरित सलेख के अन्तर्गत भारत कोककर कोयला लिमिटेड ने भारत की कोककर कोयला खानो की आयोजना, पुनर्गठन और पुनर्निर्माण के लिए पोलैड के 'मैसर्स कोपैक्स' के साथ करार किया है। मैसर्स कोपैक्स विशेषज्ञीय सेवाए प्रदान करेगे और ऐसे पुनर्गठन और पुनर्निर्माण की प्रथम प्रावस्थाओ को सम्मिलित कर साध्यता रिपोर्ट तैयार करने मे सहयोग देगे। इस प्रावस्था मे वस्तु-सूची कार्य, विभिन्न खनन खण्डो के ग्रुप बनाने के प्रस्ताव, सीमाओ का पुन. सीमाकन, उत्पादन वृद्धि के लिए प्रौद्योग-आर्थिक साध्यता का मूल्याकन और इन प्रत्येक खण्डो मे विनिधान के लिए प्रावस्थिक विकास कार्यक्रम बनाना सम्मिलित है। सहयोग की अगली प्रावस्था मे, जो बाद मे तैयार की जायगी, चयति खनन खण्डो के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करना सम्मिलित होगा। मैसर्स कोपैक्स, भारतीय अभियताओ के साथ सहयोग के लिए, पोलैड के विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त करेगे और वह पोलैड मे अनेक भारतीय अभियताओ के प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था करेगे। इस बारे मे भारतीय अभियताओ का दल पहले ही पोलैड गया है। वर्धित कोयला-उत्पादन के इस्पात सयत्रो की वितरण के लिए, क्षमता विस्तार हेतु योजनाए तैयार की जा रही है।

जहा तक इन कोयला खानो का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबध ग्रहण करने के उपरान्त कोककर कोयला खानो मे कर्मकारो के वेतन और भत्तो का प्रश्न है मजदूरी बोर्ड की सिफारिशे कार्यान्वित की गई है और प्रत्येक कर्मकार को श्रेणी I की न्यूनतम सुनिश्चित मजदूरी दी जा रही है और मजदूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई दर पर जीविका-सूची की लागत की तुलना मे परिवर्तनशील महगाई भत्ते का सदाय किया जाता है। सविदा पर कार्यशील कर्मकारो को बडी सख्या मे नियमित रोजगार दिए गए है।

†[THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI S MOHAN KUMARAMANGALAM): A statement giving the required information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

In August, 1972, 214 coking coal mines in the country have been nationalised with a view to reorganising and reconstructing them for the purpose of protecting and conserving the scarce resources of coking coal and promoting scientific development needed to meet the growing requirements for this type of coal by the iron and steel industry. Though the management of these mines was taken over by the Central Government in October, 1971, no effective steps for their reorganisation and reconstruction could be taken as the Central Government was acting as a Custodian on behalf of the private owners till the mines were nationalised in August, 1972 During this period, the production of coking coal from these mines has been more or less steady with an average monthly production of 1.08 million tonnes. This is slightly more than the rate of production which was prevailing for two months before the take-over in October, 1971. This is in spite of the teething troubles faced by

†[ ] English translation.

the new management. Steps were also taken to make available an adequate number of wagons for the transport and distribution of the coking coal to the washeries and steel plants and there have been no complaints of any shortage of such coal at the steel plants

2 The plans for the reorganisation and reconstruction of the taken over coking coal mines which have been under contemplation can now be implemented with the nationalisation of the mines in August, 1972 Under the protocol singed in January, 1972 between the Governments of India and the Polish People's Republic, Bharat Coking Coal Limited has concluded an agreement with M/s KOPEX of Poland for planning, reorganisation and reconstruction of the coking coal mines in India M/s KOPEX will give expertise and renderservices and collaborate in the preparation of feasibility reports covering the first phaseof such reorganisation and reconstruction This phase covers the inventory work, framing proposals for grouping into various mining blocks, redrawal of boundaries, assessing the techno-economic feasibility for expansion of production and working out a phased development programme for investment in each of these blocks The next phase of collaboration which will be drawn up subsequently will cover the detailed project reports for selected mining blocks M/s KOPEX will depute Polish experts for collaboration with Indian Engineers and they will also undertake the training of a number of Indian engineers in Poland A Team of Indian engineers is already in Poland in this connection Plans are also being prepared for expanding the capacity for the distribution of the increased production of coal to the steel plants

As regards pay and allowances of workers in the coking coal mines after the management of these mines was taken over by the Central Government, the recommandations of the Wage Board have been implemented and a minimum assured wage of Category I is being given to every worker and variable dearness allowance related to the cost of living index is being paid at the rate recommended by the Wage Board A large number of contract workers have also been given regular employment]

इस्पात के कोटे का आवंटन

*628 **श्री मानसिंह वर्मा :**
श्री ना. कृ. शेजवलकर :
श्री जगदीशप्रसाद माथुर :
श्री डी० के० पटेल :
श्री लाल आडवाणी :
श्री रत्तनलाल जैन :
सरदार कुमार सं० चं० आंग्रे :

क्या **इस्पात और खान** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) नट-बोल्ट आदि बनाने वाले उन कारखानो को जो छोटे कस्बो और पिछडे हुए क्षेत्रो मे स्थित है सामान्यत आवेदन देने के कितने समय पश्चात् इस्पात का कोटा आवटित कर किया जाता है,

(ख) क्या यह सच है कि इस्पात के शीघ्र आवटन के लिये छोटे उद्योगो को इस्पात के आवटन की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है, और

(ग) यदि हा, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†[ALLOTMENT OF QUOTA OF STEEL

*628 SHRI MAN SINGH VARMA :
SHRI N K SHEJWALKAR :
SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR
SHRI D K PATEL :
SHRI LAL K ADVANI :
SHRI RATTAN LAL JAIN .
SHRI S C ANGRE :

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state

(a) the length of time normally taken for the allotment of the quota of steel to the nut-bolt manufacturing small scale factories located in small towns and backward areas, after the submission of applications by them for the same;

(b) whether it is a fact that the process of allotment of steel to the small scale industries is being simplified for speedy allocation of steel, and

(c) if so the details thereof ?]

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) (क) से (ग) **आजकल**

†[ ] English translation.